महाकुंभः इस बार डुबकी के डिजिटल इंतजाम | **सहरसाः** रेलवे गुमटी है कि भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर! | **स्पैमः** भारत ने छेड़ी बड़ी जंग

22 जनवरी, 2025 60 रुपए

इंडिया टुडे

अंकल डॉन को आपकी जरूरत नहीं

आप्रवासियों को लेकर डोनल्ड ट्रंप के अतिवादी किस्म के प्रस्ताव अमेरिका में नौकरी की चाहत वाले भारतीयों की उम्मीदों को पलीता लगा सकते हैं. उनसे होने वाले नुक्सान और भारत की ओर से अपेक्षित उपायों का एक जायजा

मॉडल कहे जाने वाले बापू परीक्षा परिसर में जहां एक साथ 12,000 से ज्यादा छात्रों की परीक्षा ली जा सकती है, प्रश्नपत्र देर से पहुंचने और उसे छात्रों के कमरे में न खोले जाने की वजह से हंगामा शुरू हो गया और आखिरकार बीपीएससी ने उस केंद्र की परीक्षा को कैंसिल कर दिया.

छात्र पूरे बिहार के सभी केंद्रों की परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे और 18 दिसंबर से छात्रों ने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल में सत्याग्रह शुरू कर दिया. हमेशा की तरह इस आंदोलन को पहले पटना के खान और रहमान जैसे बड़े कोचिंग संचालकों ने लीड करने की कोशिश की, मगर आयोग की बैठक में शामिल होने की वजह से उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई थी. फिर आंदोलन स्थल पर विपक्षी राजनेताओं का पहुंचना शुरू हो गया. आखिर में प्रशांत किशोर आंदोलनकारियों से मिले.

एक ओर जहां पप्पू यादव और दूसरे दलों ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को लाठी खाने के लिए छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाया, किशोर ने अपना पक्ष रखते हुए के प्रतिनिधि मुख्य सचिव नी बात रखेंगे. इससे पहले किशोर के साथियों के साथ के पास जाते, पप्पू यादव अपने सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मिल आए. जनसुराज के नेता आर.के. मिश्र के साथ छात्र प्रतिनिधि मुख्य सचिव से मिले और अपनी शिकायतें पेश कीं. फिर पप्पू यादव भी छात्रों के साथ मुख्य सचिव से मिले.

हालांकि ऐसा लगता है कि मुख्य सचिव से मिली रिपोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हुए. इसलिए उनकी मांगें मानी नहीं गईं. 2 जनवरी की शाम प्रशांत किशोर धरने पर बैठ गए. 3 जनवरी को पप्पू यादव ने पूरे बिहार में चक्का जाम किया और भाकपा-माले और कांग्रेस के छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन किया.

अब छात्र मायूस होकर आंदोलन से दूर हो रहे हैं. प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं. भाकपा-माले और जनसुराज की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि वे इस आंदोलन को शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे. मगर जो मौजूदा हालात हैं उसमें बड़ा सवाल यह है कि वे इसे कैसे आंदोलन का स्वरूप देंगे और क्या इसकी गूंज आगामी विधानसभा चुनाव तक पहुंचेगी भी?■

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन

गोपनीयता है सबसे जरूरी

केंद्र की ओर से पेश किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का मसौदा किसी व्यक्ति के डिजिटल आचरण, उसकी पहुंच और डेटा गोपनीयता को नया रूप देने के लिए तैयार

कौशिक डेका/ ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

प्रमुख नियम क्या हैं

सुविचारित सहमति नियमों के अनुसार अब ऐप्स को सरल भाषा में यह बताना होगा कि वे कौन-सा डेटा एकत्र करेंगे और क्यों—जैसे कि संगीत ऐप के मामले में क्यूरेटेड प्लेलिस्ट के लिए आपका लोकेशन. अब बारीक प्रिंट में कोई छिपी धाराएं नहीं हैं.

नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति गेमिंग ऐप पर अकाउंट बनाना चाहता है, तो माता-पिता को तस्दीक के लिए सहमति देनी होगी.

सहमति प्रबंधक मान लीजिए कि आपने अपना डेटा किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ साझा किया है. अगर आप अपने डेटा के इस्तेमाल से सहज नहीं हैं तो इस टूल का उपयोग करके आप आसानी से अनुमति रद्द कर सकते हैं.

मजबूत सुरक्षा अब कंपनी एडवांस्ड सेक्यूरिटी उपायों को लागू करने के लिए बाध्य हैं. मसलन, शॉपिंग ऐप को आपके भुगतान डेटा को एन्क्रिप्ट करना होगा और अनधिकृत पहुंच का पता लगाने के लिए एक्सेस लॉग को ट्रैक करना होगा.

उल्लंघन की फौरन चेतावनी अगर आपके व्यक्तिगत डेटा से समझौता किया जाता है, तो फर्मों को आपको कार्रवाई योग्य कदमों के साथ तुरंत सूचित करना होगा.

डेटा रखना और मिटाना अब फिड्यूशियरी* आपके डेटा को अनिश्चित काल तक जमा नहीं रख सकते. लिहाजा, अगर आप फूड डिलिवरी ऐप का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो उसे तीन साल के बाद आपका डेटा हटाना होगा, बशर्ते उसे रखना कानूनन जरूरी न हो.

लोकलाइजेशन आपका व्यक्तिगत डेटा सीमा के है. लिह स्वास्थ्य ऐप मेडिकल डेटा को विदेश में किसी चाहता है तो उसे सरकारी पालन करना होगा.

बच्चों के डेटा की सुरक्षा एजुकेशनल ऐप के लिए बच्चों के व्यवहार की ट्रैकिंग और निगरानी प्रतिबंधित है. कोई स्कूल ऐप अटेंडेंस की निगरानी कर सकता है, पर विज्ञापनदाताओं को यह डेटा नहीं बेच सकता.

पारदर्शिता मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपके देखने के इतिहास का इस्तेमाल कैसे करता है, तो आपको अब आसानी से समझने वाली नीतियां और कॉन्टैक्ट मिलेंगे.

जवाबदेही फिड्यूशियरी को अपनी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण और ऑडिट कराना होगा. किसी वित्तीय संस्थान को तय करना होगा कि कर्ज मंजूर करने के लिए उसके एल्गोरिद्म किसी भी उपयोगकर्ता के साथ भेदभाव न करें.

** कोई व्यक्ति या कंपनी जो यह तय करता है कि व्यक्तिगत डेटा किस तरह से प्रोसेस, स्टोर और इस्तेमाल किया जाए*

CamScanner

आलोचकों को ऐतराज क्यों?

इन नियमों का मकसद कानून को इस तरह से लागू करना है कि व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा हो और साथ ही देश की नवाचार-संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले. लेकिन इसके आलोचकों ने कुछ चिंताएं जताई हैं...

- स्वतंत्र ऑडिट या अनुपालन निगरानी के लिए प्रावधानों का अभाव जवाबदेही पर सवाल उठाता है.
- सरकार और डेटा फिड्यूशियरी को छूट, डेटा प्रोसेसिंग मानकों, लोकलाइजेशन की ... पर फैसले सहित महत्वपूर्ण विवे... दिए गए हैं.
- नियम सब्सिडी, लाभ या से... सरकार को व्यापक डेटा प्रोसेसिंग... देते हैं. इन प्रावधानों में विशिष्टता का अभाव है और इनका दुरुपयोग हो सकता है.
- सरकारी संस्थाएं व्यक्तिगत डेटा को अनिश्चितकाल तक बनाए रख सकती हैं, भले ही उन्हें रखने का मकसद पूरा हुआ हो या नही. यह डेटा न्यूनीकरण सिद्धांतों का उल्लंघन है.
- तस्दीक के लायक अभिभावकीय सहमति की जरूरत अव्यावहारिक है, सरकारी आइडी को ऑनलाइन क्रेडेंशियल से जोड़ने से बड़े पैमाने पर निगरानी का जोखिम है.
- व्यापक दायित्व छोटे संगठनों और स्टार्ट-अप्स पर दबाव डाल सकते हैं, खासकर जब इकाई के आकार या उल्लंघन के पैमाने पर विचार किए बिना समान दंड लगाया जाता है.
- परामर्श प्रक्रिया केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है, यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इससे बाहर है.

नोटः मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 18 फरवरी तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं. आप innovateindia.mygov.in/dp-dp-rules-2025 पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं

माता-पिता की सहमति कैसे काम करेगी

अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया या गेमिंग ऐप जैसे किसी ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ना चाहता है, तो प्लेटफॉर्म...

- पुष्टि करें कि आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है.
- उनके माता-पिता या अभिभावक के रूप में आपसे सहमति देने के लिए कहा जाएगा
- सत्यापित करें कि आप एक वयस्क हैं और उनके वैध माता-पिता या अभिभावक हैं
- अगर आप पहले से ही उसी प्लेटफॉर्म के यूजर हैं, तो वे आपकी मौजूदा जानकारी (जैसे आपकी उम्र और आइडी) का इस्तेमाल करके पुष्टि करेंगे कि आप वयस्क हैं.
- अन्यथा वे आपके ब्यौरे—आधार, पासपोर्ट या अन्य सरकार स्वीकृत आइडी—को किसी अधिकृत एजेंसी या डिजिलॉकर जैसी डिजिटल सेवा के माध्यम से सत्यापित करेंगे.
- प्लेटफॉर्म कानून का पालन करने के लिए आपकी सहमति का रिकॉर्ड भी रखेंगे.

क्या कोई बच्चा इस प्रक्रिया को दरकिनार कर सकता है?

प्लेटफॉर्म को बच्चों को उनकी उम्र के बारे में झूठ बोलने या किसी और के अकाउंट का उपयोग करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है. अगर कोई प्लेटफॉर्म आपकी सहमति के बिना आपके बच्चे का डेटा एकत्र करता है, तो उसे 200 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

CamScanner